1	2	3
3. ब्रिटेन	ग्रामीण और अर्धनगरीय क्षेत्रो मे आपरेशन की व्यवस्था	270.00
4. अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी/स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी	भारत जनसंख्या परियोजना	615.00
5. यूनिसेफ	उत्तर प्रदेश तथा बिहार में सहायक नर्स मिडवाइफ प्रशिक्षण स्कूल	13.00
6. जनसंख्या क्रियाकलापों की संयुक्त राष्ट्र निधि	परिवार कल्याण कार्यक्रम	990.00
	योग :	2388.00
(ख) सामान के रूप में सहायता		
1. स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी	निशुल्क सप्लाई के लिए निरोध	310.00
2. जनसंख्या क्रियाकलापों की संयुक्त राष्ट्र निधि	मुख सेव्य गोलिया तथा कापर-टी लूप	24.60
3. यूनिसेफ	रोग-क्षमीकरण कार्यक्रम के लिए वेक्सीन	13.00
4 जर्मन संघीय गणतन्त्र	मास मेलिंग यूनिट के लिए उपकरण	23.16
	योग :	270.76
	कुल योग :	2758.76

भविष्य निधि संगठन के निरीक्षकों (श्रेणी-2) के पुनरीक्षित वेतनमान

2175. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भविष्य निधि संठगन के निरीक्षको (श्रेणी–2) को प्रस्तावित पुनरीक्षित वेतनमान अब तक न देने के क्या कारण है ,

(ख) सरकार का विचार उन्हें किस तारीख से पुनरीक्षित वेतन-मान देने का है; और

(ग) श्रेणी-1 तथा श्रेणी –2 के निरीक्षको के बीच विद्यमान विषमताओ को दूर करने में क्या कठिनाई है जब कि दोनों के काम का स्वरूप एकसा है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) से (ग) : भविष्य निधि निरीक्षक

(ग्रेड-2) के वेतनमान तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप पहले ही संशोधित किए जा चुके हैं। भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड-2) के वेतनमानों में पुनः संशोधन करने की मांग की गई है। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

Functioning of a Creche

2176. SHRI V. DHANDAYUTHAPANI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Creche has been functioning under NDMC at Mandir Marg, DIZ Area, New Delhi for the Children of Government employees, etc.,

(b) whether proper care is not given to the children due to unqualified staff and unsatisfactory supervision by the supervisory staff;

(c) whether standard of cleanliness is not upto the mark;

(d) whether adequate amenities are also not provided to the infants and children; and

(e) if so, the measures to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes.

(b) The Creche at DIZ area was taken over from the Minister of Home Affairs, Government of India on 1st September, 1976 alongwith staff by NDMC. Proper care is being given to the children by experienced staff and well qualified supervisory staff.

(c) Cleanlines is upto the mark.

(d) Full amenities stand provided.

(e) The question does not arise.

Leprosy Control Programme

2177. DR. SUSHILA NAYAR: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether assessment of Leprosy Control Programme shows definite improvement in areas where SET Programme has been properly worked and leprosy control units have been effectively utilised;

(b) if so, the target date by which the entire population is expected to be covered by Leprosy Control Programme; and

(c) to what extent voluntary agencies have been active in this work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) Yes, prevalence rate and total number of cases as well as infectious cases has gradually been reduced in such areas;

(b) It is proposed to cover the entire population in endemic areas of leprosy by a National Leprosy Control Programme by the end of 1982-83.

(c) Out of about 172 million endemic population under the National Leprosy Control Programme, Voluntary Organisations are covering a population of 8.14 million till March, 1976. Similarly out of 1.598 million cases under treatment, .235 million are covered by the Voluntary Organisations. Out of 37 training centres 9 are run by the Voluntary Organizations. Out of about 30,000 beds provided for National Leprosy Control Programme more than 20,000 are run by Voluntary Organizations.

श्रमिक बस्तियों में श्रमिक कल्याण के लिए योजनाएं

2178. श्री सुभाष आहूजा :
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :
क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिक कल्याण के लिए श्रमिक बस्तियों में चिकित्सालय,